MODEL ANSWER

Q. Discuss the challenges faced by refugees in accessing essential public services such as education and healthcare in India.

India has a long history of hosting refugees, including **Tibetan refugees (1959), Bangladeshi refugees (1971), Sri Lankan Tamils (1980s-90s), Rohingya refugees, and Afghan refugees**. However, India is **not a signatory to the 1951 UN Refugee Convention** or its **1967 Protocol**, meaning there is no comprehensive national legal framework to govern refugee rights.

Challenges in Accessing Education

1. **Lack of Legal Recognition & Documentation**
   - Refugees without proper documentation struggle to gain admission in government schools.
   - Many institutions demand **Aadhaar cards, domicile certificates, or birth certificates**, which refugees often lack.
2. **Language Barriers**
   - Many refugees come from non-Hindi/non-English speaking backgrounds, making it difficult for children to integrate into the Indian education system.
3. **Financial Constraints**
   - Refugees are not eligible for government scholarships and financial aid meant for Indian citizens.
   - They also lack stable employment, making private education unaffordable.
4. **Social Discrimination & Xenophobia**
   - Refugee children face **bullying, exclusion, and discrimination** in schools.
   - The perception of refugees as a **security or economic threat** affects their treatment.

Challenges in Accessing Healthcare

1. **Exclusion from Government Healthcare Schemes**
   - Refugees **cannot avail of Ayushman Bharat, Janani Suraksha Yojana**, or other government health programs.
   - They must rely on expensive private healthcare or NGO-run clinics.
2. **High Cost of Medical Treatment**
   - Without insurance or government subsidies, refugees pay **out-of-pocket expenses** for medical care.
   - Many cannot afford **medicines, surgeries, or specialist consultations**.
3. **Lack of Awareness & Cultural Barriers**
   - Many refugees are unaware of **healthcare facilities and services** available to them.
   - Cultural taboos and mistrust of Indian healthcare systems prevent them from seeking treatment.

Measures to Improve Access

- **Legal Framework** – Implement a **national refugee policy** to ensure their rights.
- **Inclusive Education Policies** – Extend **RTE Act benefits** to refugee children.
- **Healthcare Access** – Allow refugees to avail **public health schemes** and subsidized treatment.
- **Vocational Training & Livelihood Support** – Enable financial independence through skill development programs.
- **Community Awareness & Sensitization** – Reduce social discrimination through awareness campaigns.

While India's **security and resource constraints** must be considered, a **balanced approach** ensuring humanitarian protection and public service access is necessary. A **national refugee policy**, greater institutional support, and community participation can help **integrate refugees while safeguarding national interests**.

प्रश्न. भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

भारत का इतिहास शरणार्थियों को शरण देने की अपनी मानवीय और उदार परंपरा के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता की भूमि के रूप में, भारत ने समय-समय पर तिब्बती (1959), बांग्लादेशी (1971), श्रीलंकाई तमिल (1980-90), रोहिंग्या और अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी है। हालाँकि भारत ने **1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन** और **1967 के प्रोटोकॉल** पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी उसने मानवीय मूल्यों के तहत शरणार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की सहिष्णुता और मानवीय दायित्वों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

'शिक्षा तक पहुँच' में चुनौतियाँ

1. **कानूनी मान्यता और दस्तावेज़ीकरण का अभाव**
    i. उचित दस्तावेज़ों के बिना शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है।
    ii. कई संस्थान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र की माँग करते हैं, जो शरणार्थियों के पास अक्सर नहीं होते।
2. **भाषा बाधाएँ**
    i. कई शरणार्थी गैर-हिंदी/गैर-अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, जिससे बच्चों के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकीकृत होना मुश्किल हो जाता है।
3. **वित्तीय बाधाएँ**
    i. शरणार्थी भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होते हैं।
    ii. उनके पास एक स्थिर रोजगार का भी अभाव होता है, जिससे निजी शिक्षा उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है।
4. **सामाजिक भेदभाव और ज़ेनोफ़ोबिया**
    i. शरणार्थी के बच्चों को स्कूलों में बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
    ii. अक्सर शरणार्थियों को एक खतरे के रूप में देखा जाता है जो उनके प्रति बाकियों के व्यवहार को प्रभावित करता है।

Samyak
An Institute For Civil Services

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में चुनौतियाँ

1. **सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं से बहिष्कृत होना**
    a. शरणार्थी आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना या अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते।
    b. उन्हें महंगी निजी स्वास्थ्य सेवा या NGO द्वारा संचालित क्लीनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है।
2. **चिकित्सा उपचार की उच्च लागत**
    a. बीमा या सरकारी सब्सिडी के बिना, शरणार्थियों पर चिकित्सा देखभाल के लिए वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
    b. कई लोग दवाइयाँ, सर्जरी या विशेषज्ञ परामर्श का खर्च नहीं उठा पाते।
3. **जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक बाधाएँ**
    a. कई शरणार्थी स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके लिए उपलब्ध सेवाओं से अनभिज्ञ रहते हैं।
    b. सांस्कृतिक वर्जनाएँ और भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के प्रति अविश्वास उन्हें उपचार लेने से रोकता है।

सुधार हेतु उपाय

- **कानूनी ढाँचा** – उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति लागू करनी चाहिए।
- **समावेशी शिक्षा नीतियाँ** – शरणार्थी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लाभ प्रदान करने चाहिए।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच** – शरणार्थियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं और रियायती उपचार का लाभ उठाने में सक्षम बनना चाहिए।

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका में सहायता** – कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता को सक्षम बनाना चाहिए।
- **सामुदायिक जागरूकता और संवेदनशीलता** – जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को कम करना चाहिए।

जबकि भारत की सुरक्षा और संसाधन संबंधी बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए, मानवीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। एक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति, अधिक संस्थागत समर्थन और सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शरणार्थियों को एकीकृत करने में मदद कर सकती है।

Samyak
An Institute For Civil Services